The question is :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"and of prorogation of the State Assembly and recommends to the President that the Governor should be recalled forthwith."

The Motion was negatived

MR. SPEAKER : I now put Mr. Limaye's motion to the vote of the House. The question is :

"That this House disapproves the unconstitutional act of the Governor of Madhya Pradesh in not inviting immediately the new leader of the S.V.D. to form a Government which only very recently had proved its majority on the floor of Assembly."

The motion was negatived.

17.04 hrs.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd*

MR SPEAKER : Now we resume the general discussion on the General Budget. Shri Naval Kishore Sharma was on his legs. He has taken three minutes.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट पेश किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मन्त्री का भार सम्भाला है, उस दृष्टिकोण से यदि हम इस बजट को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वित्त मन्त्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे मुबारिकबाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के दायित्व को लेकर उसमें सफलता प्राप्त कर के देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पिछले साल के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात-निर्यात के बारे में जो कदम उठाये हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का सन्तुलन सुधरेगा, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रतिपादित लक्ष्यों व कर-नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर-व्यवस्था के द्वारा मध्यम वर्ग पर बोझा पड़ेगा। परन्तु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजना की शुरूआत करनी है इसलिए उस सन्दर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जोकि तकलीफ उठाकर भी कुछ दे सकते हैं उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मन्त्री के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं बड़ी नम्रतापूर्वक कि वित्त मन्त्री महोदय ने किसानों पर जो नये कर लगाये हैं, उनके ऊपर वे पुनर्विचार करें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मन्त्री द्वारा उर्वरकों पर जो कर लगाया गया है, जो ड्यूटी लगाई गई है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की प्रस्तावना के पैरा नं० 6 में कृषिजन्य कच्चे माल के उत्पादन के लिये पूंजी लगाने की आवश्कता महसूस की है। जब उनकी खुद की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, एकमात्र तरीका कहा जा सकता है, उस पर आधारित खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि वित्त मन्त्री महोदय अपनी ही बात को, अपने ही द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के द्वारा तो काट नहीं रहे है।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा बल्कि 18 या 20 प्रतिशत भूमि ही ऐसी है जोकि सिंचित भूमि के नाम से पुकारी जा सकती है। ऐसी दशा में इस देश के अधिकतर किसान बंजर या असिंचित भूमि पर ही खेती करते है। उन किसानों को आज भी भगवान के ऊपर मुनहसिर रहना पड़ता हैं। हिन्दुस्तान के अधिकतर किसान अभी भी आसमान की ओर देखते हैं। उनके भाग्य का फैसला इन्द्र भगवान ही करते हैं। अगर वारिश हो जाती है तो उनकी खेती में कुछ पैदावार हो जाती है और अगर वर्षा नहीं हुई तो पैदावार नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो किसान खाद का इस्तेमाल करते हैं उस खाद के ऊपर, जैसा कि कहा गया हैं, 8 रुपये बोरी यूरिया पर और 5 रुपये बोरी आमोनियम सल्फेट पर बढ़ जायेगा। यह बात सर्वमान्य है कि इस देश के अधिकतर किसान जो कि छोटे किसान है, वे 20 से लेकर 25 बोरी तक खाद इस्तेमाल करते हैं और वह खाद भी कोआपरेटिव सोसायटी से उधार लेकर इस्तेमाल करते हैं। इस खाद पर यदि उन को 200-250 रुपये अधिक देना पड़ेगा तो क्या उनके साथ यह ज्यादती नहीं होगी? आप कल्पना कीजिए, मैं खास तौर पर अपने इलाके राजस्थान की बात करना चाहता हूँ, जहां हर साल अकाल पड़ता है, उस इलाके में यदि इतनी महंगी खाद लेकर किसान खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहे तो मैं समझता हूँ कि उसको यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इतनी महंगी खाद का उपयोग खाद्य उत्पादन में करे या न करे। इस का परिणाम यह होने वाला है कि देश में जिन किसानों ने खाद के जरिये से, नई टेकनिक के जरिये से खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कुछ कारगर कदम उठाये है और जिस से अब वह थोड़ा-सा महसूस करने लगे हैं कि वह देश के अन्नदाता हैं, खुद भूखे और नंगे रह कर देश के लोगों को अन्न देते हैं, उसके भी कुछ अच्छे दिन आने लगे थे और वह महसूस करने लगे थे कि उनका भाग्य चमकने वाला है, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस कर-व्यवस्था के द्वारा उन पर चोट पहुंचाई है वह अपने आप में बहुत बड़ी चोट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वैसे ही हमारे देश में जो खाद की खपत है वह दुनिया के देशों में सब से कम है। हमारे यहां खेती में 4.00 पर-हेक्टर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में इससे सात गुनी अधिक खाद इस्तेमाल की जाती है। ऐसी स्थिति में जबकि हम अभी तक भी, पिछले सालों तक भी देश में खाद के लिए लोगों को उर्वरकों के लिए सबसिडी देते रहे हैं तब इस तरह की ड्यूटी लगाना अपने आप में एक ऐसी बात है जिसका कि कोई जवाब नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्त मन्त्री द्वारा जो यह खाद पर ड्यूटी लगाई गई है यह एक ऐसी ड्यूटी है कि जिस पर पुर्नविचार करना आवश्यक है।

वित्त मंत्री द्वारा पम्पिग सेट्स पर लगाई गई ड्यूटी का भी मैं विरोध करना चाहता हूं। जिन पम्पिग सैट्स के जरिये किसान लोग और वह छोटे किसान लोग हैं जोकि अपने खेतों में पानी देना चाहते हैं, जिसके जरिये वह बैलों की दिक्कतों से बचना चाहते हैं, जिसके जरिए वह एग्रीकल्चरल लेवर को कम करना चाहते हैं उस काम में वित्त मन्त्री जी ने यह पम्पिग सैट्स पर टैक्स लगा कर और वह टैक्स 20 परसैंट लगा कर एक ऐसा काम किया है जिसकी कि कभी तारीफ नहीं हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मन्त्री जी शायद ऐसे लोगों के प्रभाव से आ गये हैं, उन आयोजकों के प्रभाव में आ गये हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स और उन एकनोमिस्ट्स के प्रभाव में आगये है जिन्हें मैं फैशनेबुल एकोनामिस्ट्स कहना चाहता हूं और जिन्होंने कि नारा दिया है कि देश

में चौथी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए इस बात की आवश्यकता है कि कृषि साधनों को टैप किया जाय और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय। लेकिन मेरी समझ में कृषि साधनों पर टैक्स लगाने की स्थिति अभी इस देश में नहीं आ रही है। आज आपने किसानों के लिए क्या किया है? आपने किसानों के लिए कौन-सी ऐसी नई बात की है जो आप कृषि साधनों को टैप करने की सोच रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि बिजली आपने किसानों को दी है तो मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि वह बिजली भी आप बाकी लोगों के मुकाबले में उन को सस्ती नहीं देते हैं, महंगी देते रहे हैं और इसके बावजूद भी उनसे मिनिमम चार्ज के नाम पर पैसा वसूल करते रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ और बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सिंचाई की सुविधायें आपने किसानों को दी हैं तो किसानों को उसके लिए बैटरमेंट लेवी के नाम पर रुपया देना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि सिंचाई की दरों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसका भी उसे भार वहन करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि असल में किसान के लिए अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में जिसके कि अनुपात में यह कहा जाय कि किसान की ज्यादा अवस्था सुधर गई है। आज भी हिन्दुस्तान के गांवों की हालत बदतर है। आज भी वहां पर सड़कें नहीं हैं। आज भी वहां पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। आज भी वहां दवादारू का इंतजाम नहीं है। अगर हम हिन्दुस्तान के गांवों को सुधारना चाहते हैं अगर हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो हमें हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वालों की हालत को सुधारना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। इसलिए मैं वित्त मन्त्री को कहना चाहता हूँ कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसमें किसान टैक्स दे सकें। आप उद्योगों को संरक्षण देते हैं और 5 साल के लिए टैक्स होलिडे की उनके वास्ते घोषणा की है। अभी कल ही सेठी साहब ने कॉटन टैक्सटाइल के मिल के लेबरर्स को सहायता देने के लिए कहा है और क्योंकि 50 लाख मजदूरों का सवाल है इस लिए उनको रिबेट दिया गया है। जब इस देश के 37-38 करोड़ किसानों का सवाल हो और जबकि उनके पास आमदनी भी उतनी न हो जिससे कि उनका जीवन समुचित रीति से चल सके, जीवनस्तर उनका गिरा हुआ हो तब इनडाइरेक्ट तरीके से उनके ऊपर टैक्स लगाना यह बाजिब नहीं कहा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो गांवों के रहने वाले लोग हैं, गांवों के किसान हैं उनकी आमदनी हिन्दुस्तान के कस्बों और शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कम से कम आमदनी से भी कम है। यह बात निश्चत तौर पर कही जा सकती है। ऐसी अवस्था में मेरा यह निवेदन है कि किसान अभी ऐसी अवस्था में नहीं आये हैं कि उन पर टैक्स लगाया जाय। जब उनकी अवस्था सुधर जाए, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो तब मुझे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप उन पर टैक्स लगायें।

कहा जाता है कि उन पर टैक्स लगाने का विरोध केवल चन्द लोग कर रहे हैं। इसका विरोध वह लोग कर रहे हैं जोकि बड़े किसान हैं पर मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े किसानों का शायद इस से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान अगर होने वाला है, कमर टूटने वाली है तो वह छोटे किसानों की टूटने वाली है। इसलिए इस बात पर एक मानवीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह दोनों ड्यूटीज ऐसी हैं और जैसी हमारी व्यवस्था है उसमें वित्त मन्त्री जी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। केवल 24 करोड़ रुपये का सवाल है। 24 करोड़ रुपये की कमी हमारी जो दूसरी खर्च की मदें हैं उनमें कमी करके कर सकते हैं। माननीय

[श्री नवल किशोर शर्मा]
राज्य मन्त्री ने कल कहा था कि खर्च की कमी की तो बात सब करते हैं लेकिन कोई इस तरीके की बात नहीं बतलाता और कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं दिया गया है जिसके कि द्वारा खर्च में कमी की जा सके।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले चन्द सालों में ब्यूरोक्रेसी का और नौकरशाही का जिस तेज गति से विस्तार हुआ है उसकी ओर जरा वह दृष्टिपात करें। यह नौकरशाही जोकि बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेती है और जिसके कि रोज झगड़े आपके सामने आते हैं और जैसा कि मैंने बतलाया उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन इसके बावजूद उसकी एफिशिएंसी गिरती जा रही है। कोई वजह नहीं है कि उस पर रोक क्यों न लगाई जाय? लेकिन हम देखते हैं कि रोक लगाई जाती है चपड़ासियों की नियुक्ति पर, रोक लगाई जाती है फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की भरती पर। मैं कुछ आंकड़े देकर यह सिद्ध करना चाहता हूं कि हमारे देश में जहां सन् 1961 में इन सैक्रेटरीज जनरल, सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज और एडीशनल सेक्रेटरीज आदि की संख्या 50 थी वहां वह संख्या सन 65 में बढ़ कर 64 हो गई और उस के बाद से वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से डिप्टी सेक्रेटरीज जिनकी कि संख्या सन 1961 में 193 थी वह सन 1965 से बढ़कर 223 हो गई है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या में और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी संख्या में बड़ी तेज गति से वृद्धि हुई है जहां यह संख्या 1960 में 28 लाख 57 हजार थी वहां सन 1966 के अन्दर संख्या बढ़ कर 37 लाख 66 हजार हो गई है। यह तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के आंकड़े मैंने दिए। उसी तरीके से जहां 1956 में सैंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संख्या 17 लाख 92 हजार थी वहां सन 1963 में वह बढ़ कर 25 लाख 36 हजार हो गई है।

एक माननीय सदस्य : मंत्रियों की भी तो संख्या बड़ी तेजी से इन वर्षों में बढ़ी है।

श्री नवल किशोर शर्मा : ठीक है मैं मानता हूं कि मंत्रियों की भी संख्या इस देश में बेतहाशा बढ़ी है। इन सब पर रोक लगाई जानी चाहिये। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप डिफेंस के खर्च को कम करें। देश की सुरक्षा के लिए आपने डिफेंस के खर्च में जो बढ़ोतरी की है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जो ऐसा अनावश्यक खर्चा है, ज्यादा खर्चा है ऐसे अपव्यय पर उनको रोक लगानी चाहिए।

आज भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में कोई 500 कमेटिया काम करती हैं। यह 500 कमेटियाँ मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों के अलावा है तो क्यों नहीं ऐसे खर्चे को और जोकि अपव्यय की तारीफ में आता है उसको रोका जाय और क्यों न उनको रोक कर पैसा बचाया जाय ताकि किसान को इस अनुचित बोझ से बचाया जा सके।

इसके साथ-साथ दो शब्द मैं और कहना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जोकि राजनैतिक बैकग्राउण्ड के कारण एक पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। राजाओं का राज्य होने के कारण यहां के जो विभिन्न इलाके है उनका उतना विकास नहीं हो पाया है। उसके क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नम्बर का प्रांत होने के बावजूद उसका समुचित विकास नहीं हुआ है और दुर्भाग्य से हर साल पड़ने वाले अकाल उसकी आर्थिक व्यवस्था को और भी अधिक जर्जर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने राजस्थान के लिए तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है और उसके लिए मैं उनका आभारी हूं लेकिन फिर भी यह व्यवस्था काफी नहीं है और राजस्थान के विकास के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल एक ऐसा प्रोजैक्ट है जिसके पूरा होने पर देश के खाद्यान्न का जो मसला है वह हल हो जाने वाला है।

राजस्थान सरकार अपने आर्थिक साधनों में इस काम को पूरा नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपया इस बात की घोषणा करें कि राजस्थान कैनाल का काम सेन्टर द्वारा अपने हाथ में लिया जायेगा।

इसके साथ-साथ मैं राजस्थान में पड़ने वाले अकाल के इलाज के लिए भी उन से स्थायी हल की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के इन अकालों के सम्बन्ध में और जो अन्य दैवी प्रकोप होते है उनके सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कोई ऐसा फण्ड कायम किया जाये, कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिसके जरिए से इन होने वाली हानियों के बारे में कुछ निश्चित कदम उठाए जा सकें।

मैं वित्त मन्त्री जी से फिर यह दरख्वास्त करूंगा कि जहां उन्होंने देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का अच्छा काम किया है वहां किसानों के साथ भी उनके द्वारा न्याय होना चाहिए। मेरी मान्यता है कि वे गांधीवादी पुरुष हैं। यह गांधी शताब्दी का साल है। चूंकि गांवों के विकास के पक्ष में गांधीजी की निश्चित मान्यता थी, इस लिए इस गांधी शताब्दी के साल में गांवों के विकास में रोड़े बन कर कोई योजना वह देश के सामने नहीं पेश करेंगे, ऐसी मुझको आशा है।

MR. SPEAKER : Shri D. B. Raju; maiden-speech.

SHRI D. B. RAJU (Narasapur) : Mr. Speaker, Sir, I rise to support the budget proposals that have been presented to the House by the hon. Finance Minister. It is indeed a very difficult task for any Finance Minister to frame the budget of a country like ours. He could not ignore, the economic conditions that obtain in this country and he could not ignore the kind and extent of the resourrces that we have. I thank the Finance Minister for providing relief to stimulate our exports ; the reduction in the export duty on jute, tea and mica is a welcome measure which may accelerate the increasing trend in exports and we will be able to find a bigger foreign market for our goods. The proposal for increasing the value of imported motor-cars also is a good one. The proposal to convert the existing specific rates into *ad velorem* rates for certain items is also a welcome measure.

As regards the imposition of a tax on sugar, an essential item of consumption, it is not justifiable. Government should have to see that adequate quantities of sugar are released for free sale at the appropriate time. This would avoid hardships to the consumer in the rural areas and also help them in getting sugar at reasonable prices. There is also no justification for raising the rates of duty on processed food and domestic electrical appliances.

The Finance Minister in his budget speech had referred to the increase in food production and the necessity for further increase in order to ensure satisfactory levels of consumption for our growing population. But, are the new imports proposed now in line with the avowed policy of the Government in promoting agriculture ?

The excise duties on fertilisers, oils and pump-sets are bound to affect agricultural production. It is well known that the increase in production is due to the favourable weather conditions and to the new agricultural strategy which has just started paying intensive cultivation and extensive use of fertilisers and the introduction of the the high-yielding varieties are the main ingredients of the new agricultural strategy.

With the imposition of 10 per cent *ad valorem* tax on fertilisers, the prices which are already at a high level are sure to rise, which in turn may affect the cost of production of foodgrains. Similar is the case with the proposed 20 per cent *ad valorem* tax on power-driven pump-sets. Small cultivators and farmers on the margin have to borrow money from the banks to purchase fertilisers and pump-sets. Borrowing from the banks is not possible below a rate of interest of nine or 10 per cent. The cost of credit, the cost of borrowing, in an essential ingredient of the cost of production in every aspect of of our economy. There cannot be any industry, any trade, which can function

[Shri D. B. Raju]

without borrowing. That is also adding to the cost of production. Every little thing in every aspect of life is adding to the cost of living.

Both these levies will considerably affect the people especially in Andhra Pradesh which is a predominantly agricultural State, consuming large quantities of fertilisers and also having the largest number of power-driven pump-sets in the country next to Tamil Nadu.

To impose these levies at this stage of agricultural development is just like killing the goose which started laying golden eggs. These levies should not be imposed until we reach a sufficiently high and stable level of of agricultural production.

The proposed wealth tax on agricultural lands including the houses standing on it is also not a sound proposition. This proposal even though the theoretically sound from the point of view of equity, is very complicated and difficult in practice. Complications as to the competency of the Centre to levy such a tax, and identification of the genuine agriculturist for purpose of exemption are there. Valuation of agricultural lands is a very complicated one.

The great scope for difference in valuation leads to corruption and so on. If agriculture is sound, steady and prosperous, then our country will be sound, steady and prosperous. If unnecessary and wasteful expenditure had been cut down, we would have balanced the budget without additional taxation on landed properties.

In the public sector undertakings where huge investments were made, the returns are not adequate and are not upto expectation. Every effort should be made to ensure that the public sector undertakings should be as efficient as the private sector units operating in similar fields. Therefore, I appeal to the Finance Minister to drop this agricultural wealth tax.

To maintain law and order in the country is becoming more and more expensive. There is a general growth of lawlessness and disorder throughout the country under one name or another. There are riots and disturbances in systematic and organised attacks on human lives and properties in the name of language and sometimes in the name of Senas and sometimes in the name of implementation of safeguards and so on. In many cases, politicians or other scheming persons from behind by instigating innocent students and youths are creating lawless activities in some parts of the country and the result is the senseless destruction of public properties and human lives and dislocation of the law and order situation. The motives of politicians are always clouded in ambiguity. One does not know how their eternally interpretable actions or statements should be regarded at any specific moment before, during or after such a storm. The first claim of any citizen in the country is of security of life, property and honour. The Government should be firm in dealing with anti-social elements and see that there is no repetition of such kind of incidents in any part of the country.

17.29 hrs.

[**Shri R. D. Bhandare** *in the Chair*]

I appeal to the hon. Members whichever side they are that we should get together to overcome these lawless elements of to-day and we should give correct lead to the people as well as younger generations in order to abide by the Constitution and parliamentary methods.

With these words, Sir, I support the Budget.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, संसद् के पिछले अधिवेशन में जब वित्त मन्त्री से यह पूछा गया कि दुनिया के दूसरे देशों का हमारे ऊपर जो ऋण है उसका ब्याज हम को कितना देना पड़ता है तो वित्त मंत्री जी ने बताया था कि 163 करोड़ रुपया हम को ब्याज का देना पड़ता है। मुझे पता नहीं कि उसके बाद जो ऋण हमारे देश ने दुनिया के दूसरे देशों से लिये हैं उन से यह राशि कितनी बढ़ गई है और आज उसकी स्थिति क्या है और कितना ब्याज हम को उस ऋण के ऊपर देना पड़ता है ? लेकिन मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। केन्द्रीय सरकार के परिवार नियोजन विभाग ने भारतवासियों में परिवार नियोजन की प्रवृत्ति जगाने के लिए

एक नई पद्धति अपनाई है। वह प्रतिदिन देश में जन संख्या की कितनी वृद्धि हुई है, यह समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाते हैं। ताकि देशवासियों को यह ज्ञान हो कि हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनका झुकाव परिवार नियोजन की ओर हो। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की परम्परा वित्त मंत्रालय भी अपनाये। हमारे देश पर दुनिया के दूसरे देशों का कितना ऋण है और वह ऋण कुल मिला कर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना बैठता है और उसका ब्याज कितना बढ़ता जा रहा है? इसका एक विवरण भी अगर प्रति दिन नहीं तो कम से कम प्रति मास या त्रैमासिक समाचारपत्रों में प्रकाशित अवश्य करवाया जाना चाहिये। इससे हमारे देशवासियों के अन्दर यह प्रवृत्ति जगेगी कि हम दुनियां के दूसरे देशों के अधिक ऋणी न होते जांय और अपने पैरों पर खड़े हो कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और उसके लिए उपाय खोजें। वित्त मन्त्रालय का भी इस ओर ध्यान रहेगा कि हम दुनिया के दूसरे देशों के अधिक ऋणी होते चले जा रहे हैं। हमें धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। यथा सम्भव दुनिया के दूसरे देशों से ऋण लेने की प्रवृत्ति में हाथ खींच कर हम को काम करना चाहिये।

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन ने अभी कुछ दिन पहले श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया था जिससे सीधे टैक्सों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था। मुझे पता नहीं कि कब तक उसकी रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखी जाएगी। लेकिन जैसा समाचारपत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है उस में यह बात है कि जो छोटे छोटे करदाता हैं उन करदाताओं से कर वसूल करने के लिए सरकार ने भारी मशीनरी लगा रखी है। उस पर सरकार का जो व्यय होता है, उसकी बजाय अच्छा यह हो कि उन पर कुछ कम्पाउंड टैक्स लगा दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो सरकार का जो इस भारी मशीनरी में व्यय होता है, उस से सरकार बच सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार का सुझाव दिया गया है। यदि दिया है तो वित्त मन्त्रालय ने उसके ऊपर अभी तक विचार किया है या नहीं किया है? इस साल का वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस में उन्होंने उस दिशा में कोई संकेत नहीं दिया है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार अभी तक इस में अपना कोई मन नहीं बना सकी है।

तीसरी बात गाँवों से नगरों की ओर जो सुविधायें सिमट सिमट आती चली जा रही है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इस बारे में हमारी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और इसके बारे में कुछ करना चाहिये। कुछ दिन पहले योजना आयोग के एक सदस्य ने जो इस समय गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं, श्री श्रीमन्नारायण ने एक बात सार्वजनिक रूप से कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शहरों में इसी तरह से बराबर सुविधायें सिमटती हुई चली गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब गाँव उजड़ जायेंगे। शहरों में निवास की पूरी व्यवस्था नहीं होगी और इस बढ़ती हुई आबादी के बोझ को शहर सम्भाल नहीं सकेंगे। इससे देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसके अन्दर एक बहुत बड़ी विषमता पैदा हो जाएगी। दुर्भाग्य से अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई व्यवहारिक निर्णय नहीं लिया है जिससे पता लगता हो कि शहरों की तरह ही सुविधायें गांवों की ओर भी थोड़ी-थोड़ी करके वह प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है। इससे लोग गांवों की ओर भी आकर्षित होंगे और शहरों की सुविधाओं से प्रभावित हो कर वे उनकी ओर दौड़ते नहीं चले जायेंगे।

कुछ दिन हुए यहीं पर एक प्रश्न पूछा गया था कि गांवों के अन्दर जो सरकारी अस्पताल हैं उन में कितने अस्पताल ऐसे हैं जो बिना डाक्टरों के चल रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े बताता हूँ। जिस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था तब इसी सदन के अन्दर सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था

[श्री प्रकाशवीर शस्त्री]

कि लगभग सात सौ अस्पताल उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हैं जो बिना डाक्टरों के चल रहे हैं। यह स्थिति क्यों है ? गांवों के अन्दर डाक्टर क्यों नहीं जाना चाहते ? इसका एक कारण यह भी है कि मैडीकल कालेज ज्यादातर शहरों में हैं। जो डाक्टर वहां पर पढ़ते हैं वे शहर की सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। इसलिए वे अपने नौकरी काल में भी शहरों में ही रहना चाहते हैं, गांवों में जा कर सेवा करना नही चाहते हैं। सरकार उनको गांवों में भेजने के उपाय ढूंढती है। उनको कुछ अतिरिक्त वेतन देने की बात करती है ताकि वे गांवों की ओर आकर्षित हों। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे देश में जितनी भी टैक्नीकल संस्थायें है अगर वे शहरों की अपेक्षा गांवों के बातावरण में हो तो गांवों के बच्चे अपने घर में भी रह सकते हैं और टैक्नीकल एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उस बातावरण में दीक्षित डाक्टर, इंजीनियरों को आदि जो है, उनको गांवों में ही रह कर कार्य करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। और यह जो भय बढ़ता चला जा रहा है कि सुविधायें गांवों से सिमट कर शहरों की ओर आती जा रही हैं, उस में भी कमी आती चली जाएगी।

अब मैं टैक्नीशियनों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ। श्रीमती इन्दिरा गांधी जब रुड़की विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने गई थीं तब वहां के स्नातक जो इंजीनियर बन रहे थे, उन्होंने जब उनको डिग्री दी जाने लगी तो कहा कि हमें उपाधि नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिये। इसी तरह का एक प्रदर्शन चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कालेज में भी हुआ था। पिछली बार देश के इंजीनियरों ने काफी दिनों तक हड़ताल और प्रदर्शन का भी सहारा लिया था। उस समय इस विभाग से पूछा गया कि हमारे देश में इस समय बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या कितनी है ? तो बताया गया कि लगभग साठ हजार इंजीनियर हमारे देश में बेरोजगार हैं। यह संख्या जो उस नये वर्ष के निकलने वाले स्नातक हैं उन से अलग है। उनको भी अगर जोड़ा जाए तो उनकी संख्या अस्सी हजार के लगभग हो जाती है। गुजरात की सरकार ने इसके लिए एक उपाय सोचा है। उसने कुछ राशि रखी है और बेरोजगार इंजीनियरों से पूछा है कि कितने लोग इस प्रकार के हैं जो सर्विस के माध्यम से काम करना चाहते है ? और कितने इंजीनियर इस प्रकार के हैं जो उनको अगर सरकार कुछ आर्थिक सुविधायें दे तो वे अपने पैरों पर खड़े हो कर छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए, विशेषकर टैक्नीकल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त की है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए गुजरात जैसी योजना हर प्रान्त को चलानी चाहिये। इस दिशा में वित्त मन्त्रालय को प्रान्तीय सरकारों को कुछ निर्देश देने चाहिये। केन्द्रीय सरकार इस दिशा में स्वयं आगे आ कर कुछ योजना प्रस्तुत कर सके तो वह बहुत अच्छी बात होगी।

जहाँ तक टैक्सों की बात है, उनमें जितने टैक्स इस समय हमारे देशवासियों पर लगे हुए हैं अगर ये सारे के सारे विधिवत वसूल कर लिए जायें तो हिन्दुस्तान में कोई नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज सब से बड़ी कठिनाई यह है कि हर प्रान्त के बजट में कुछ नए टैक्स हर वर्ष लग जाते हैं लेकिन टैक्सों की वसूली की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक छोटे से बिजनौर जिले में चीनी और खण्डसारी बनाने वाले जो क्रशर हैं उनकी संख्या 2200 है। खंडसारी क्रशरों की देखरेख करने वाले जो इंस्पैक्टर हैं उनका हर क्रशर के साथ अपना ढाई सौ रुपया प्रति मास बंधा हुआ रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि पच्चीस हजार रुपया जो सरकार को एक क्रशर से मिलने वाला होता है वह मिलने से रह जाता है। अब आप

ही बताइये कि एक क्रशर से पच्चीस हजार रुपया जो सरकार के पास आने वाला था अगर वह छूट जाता है तो 2200 क्रशरों से सरकार का कितना रुपया वसूल होने से छूट गया ? एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सरकार ने इसको रोकने के लिए एक दूसरा काम किया । ये जो क्रशर चलते हैं इन में बिजली इस्तेमाल होती है । सरकार ने कहा कि देखा जाए कि जब इतनी बिजली इस्तेमाल हुई है तो इतनी कम खण्डसारी पैदा क्यों हुई, या इतनी कम चीनी पैदा क्यों हुई । इसका असर यह हुआ कि एक दूसरी प्रकार की चोरी शुरू हो गई । पहले खंडसारी के इंस्पैक्टरों के साथ ही उनका लेन देन था अब उन्होंने बिजली के इंस्पैक्टरों के साथ भी सांठगांठ कर ली । इस तरह से जो लाखों रुपया बिजली के द्वारा सरकार के पास आने वाला था वह मीटरों में परिवर्तन करवा कर, बिजली के माध्यम से उन्होंने बचा लिया और यह भी सरकार को नुकसान हुआ । यह स्थिति केवल एक विभाग की है । सरकार ने जितने इस प्रकार के टैक्स लगाये हुए हैं सबमें यह गड़बड़ है । तम्बाकू पर तम्बाकू के इंस्पैक्टर है और वे वहां गड़बड़ करते है । इसका नतीजा यह होता है कि दो ढाई सौ रुपया महीना पाने वाला इंस्पैक्टर लाखों रुपया एक साल में कमा लेता है । सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं अगर इनकी वसूली का पूरा प्रबन्ध हो जाए तो सरकार को नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है । सरकार जहां नए टैक्सों का प्रावधान करे, वहां इस बात की भी व्यवस्था करे कि जो पहले से टैक्स लगे हुए हैं, उनकी वसूली भी ठीक तरह से हो और उन टैक्सों में किसी प्रकार की कटौती न हो ।

जहां तक कृषि सम्पत्ति कर का सम्बन्ध है सब से पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में निर्णय लेने में हाथ किस का है ? समाचारपत्रों में चर्चा यह है कि इस समय वित्त मंत्री जी की उसी तरह से आलोचना हुई है जैसे आलोचना उनकी स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम जब वह लाये थे तब हुई थी । इसका स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिये कि इस योजना को लाने के पीछे किस का हाथ है ? समाचारपत्रों में यह समाचार आया है कि चूंकि मध्यावधि निर्वाचन होने थे, इस वास्ते इस को पहले प्रकट नहीं किया गया । यद्यपि कृषि कर के सम्बन्ध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गाडगील ने प्रधान मन्त्री को जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं, कृषि कर के बारे में पूरी योजना दे दी थी । लेकिन उसको इस वास्ते दबा कर रख लिया गया कि मध्यावधि निर्वाचनों में कांग्रेस की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसलिए सोचा गया कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद इस योजना को प्रकाश में लायेंगे । क्या यह सच बात है ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं । साथ ही यह भी पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह किस के मस्तिष्क की उपज है, कौन इसका जन्मदाता है ? किसान के अन्दर एक इससे भय व्याप्त हो गया है । गांवों में एक कहावत है उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना । इस कृषि सम्पत्ति कर से किसानों के अन्दर यह भय बैठ गया है कि अभी तो सरकार ने कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है लेकिन धीरे-धीरे सरकार का इरादा यही है कि कृषि पर कर लगाना चाहिये । छोटे-छोटे किसानों के अन्दर भी यही भय व्याप्त हो गया है, बड़ों के अन्दर तो हुआ ही है । सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वह इस कृषि सम्पत्ति कर को उन लोगों पर लगाना चाहती है, जिन के पास ब्लैक का बहुत अधिक धन था और उस को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए जिन्होंने बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस ब्लैक पैसे को सफेद करने में देश का कृषि-उत्पादन बढ़ सकता हो, तो सरकार को यह सोचना चाहिए था कि क्या यह कर लगाना उचित है ? लेकिन जब सरकार ने कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का निर्णय कर ही लिया है, तो क्या उस ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि यह कर केवल उन्हीं लोगों से लिया जायेगा, जिन के पास ब्लैक के करोड़ों अरबों रुपये थे और उन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

को सफेद करने के लिए जिन्होंने बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट रूप से देश को बताना पड़ेगा। क्योंकि इस कर की घोषणा से किसानों में बड़ा भारी आतंक फैल गया है। लोगों को यह आशंका होने लगी है कि सरकार कृषि सम्पत्ति के बहाने धीरे-धीरे कृषि पर कर लगाना चाहती है।

इस भय का कारण सरकार द्वारा खाद पर कर लगाने की घोषणा है। अब तक स्थिति यह थी कि बाहर से मैक्सिकन वैरायटी के जो नये बीज आये थे, उनके द्वारा हमारे देश की कृषि में क्रान्ति आई थी। किसान उत्साहित हो कर कृषि-कार्य में जुट गये थे। रामायनिक खाद, पानी और ऋणों की व्यवस्था करके उन्होंने अपनी उपज में वृद्धि की थी। जिस प्रकार दूध में उफान आने पर उसमें पानी डाल कर झाग को नीचे दबा दिया जाता है उसी प्रकार इस बजट में खाद पर टैक्स लगाने की घोषणा से किसान के उत्साह पर पानी पड़ गया है।

उत्तर प्रदेश में स्थिति यह थी कि वर्षा न होने के कारण हाहाकार मचा हुआ था; किसानों ने मैक्सिकन वैराइटी के बीजों का उपयोग किया। बिजली के छोटे छोटे पम्प खरीदे और उन के द्वारा सिंचाई कर के खेती के उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन इस बजट में बिजली द्वारा चालित पम्पों पर भी टैक्स लगा दिया गया है।

इसके अलावा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर टैक्स लगाने का परिणाम यह हुआ है कि किसान का गन्ना सस्ता हो गया है। मिलें कहती हैं कि हम पर जो टैक्स लगेगा, वह हम कहां से लायेंगे? उसके लिए हम किसान से गन्ना सस्ता लेंगे। किसान पर इस बजट के द्वारा यह भी एक चोट पड़ी है। कृषि सम्पत्ति कर की घोषणा, खाद और बिजली से चलने वाले पम्पों पर टैक्स और चीनी पर टैक्स बढ़ाने के कारण गन्ने का सस्ता हो जाना, इस प्रकार किसान पर दोहरी मार पड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस बजट ने सीधे रूप में किसी की कमर तोड़ी है, तो वह किसान की।

वित्त मंत्री को सुन कर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन श्री गुप्त की सरकार ने शपथ ली, उसके अगले दिन से ही उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने गन्ने का भाव एक रुपया सस्ता कर दिया। इस बारे में कोई विधिवत् घोषणा नहीं की गई। लेकिन श्री गुप्त की सरकार बनने के अगले दिन से ही गन्ने का भाव एक रुपया सस्ता हो गया। आखिर इसका क्या कारण है कि श्री गुप्त के गवर्नमेंट में आते ही चीनी मिलों में इस प्रकार की उलटी क्रान्ति आ गई?

मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि किसी वस्तु के मूल उत्पादक को उसके उत्पादन का मूल्य पैसे के साथ-साथ कुछ मात्रा में उसके उत्पादन की शक्ल में भी दिया जाये। उदाहरण के लिए कपास के मूल उत्पादक को कपास का मूल्य केवल पैसे की शक्ल में ही न दिया जाये, बल्कि कुछ मात्रा में मिल रेट पर कपड़े की शक्ल में भी दिया जाये। इसी प्रकार गन्ने के मूल उत्पादक को 100 रुपये में से 98 रुपये तो पैसे की शक्ल में दिये जायें, लेकिन दो रुपये उस को चीनी की शक्ल में भी दिये जायें ताकि उस को चीनी के परमिट के लिए तहसीलदार और एस० डी० एम० के पास न जाना पड़े और वह भी अपने बच्चों के मुंह में चीने के दो दाने रख सके।

मैं वित्त मंत्री को एक नये कर का भी सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने थाईलैंड में देखा है कि उन्होंने अपनी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक साइनबोर्ड टैक्स लगाया है। उसका अभिप्राय यह है कि जो लोग अपनी दुकानों पर थाईलैंड की देशी भाषाओं के साइनबोर्ड लगायेंगे उन पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जो विदेशी भाषाओं के साइनबोर्ड

लगायेंगे, उन पर टैक्स लगाया जायेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने नगरों को थाईलैंड की भाषाओं के सानबोर्डों से भर दिया है। वित्त मंत्री को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए।

मेरे पास यह एक कपड़ा है, जिसको कैनवेस कहा जाता है। इस पर सरकार ने टैक्स लगाया है। यह कपड़ा पावरलूम के द्वारा पिलखुआ, हापुड़ और मेरठ आदि में बनाया जाता है इस का भाव डेढ़ रुपया मीटर है। दूसरी ओर मिलों में बनाया जाने वाला कैनवेस है, जिस का मूल्य आठ रुपये मीटर है। पावरलूम के द्वारा जो कैनवेस बनाया जाता है, उसके लिए पावरलूम तो चलती है, लेकिन बाकि सारा काम हाथ से होता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण किया जाये क्यों कि यह टैक्स लगाये जाने से पिलखुआ जैसे छोटे शहर में 250 कारखानों के बन्द होने और उसके परिणामस्वरूप 12,000 मजदूरों के बेकार होने की आशंका है। सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि उसका उद्देश्य कुछ हो और उसकी कार्यवाही का परिणाम कुछ दूसरा ही निकले। इसलिए करों की व्यावहारिकता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : सभापति महोदय, खेती पर वैल्थ टैक्स के बारे में जो प्रोपोजल है, सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे डिफर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों की डेवेलपमेंट के बाद हमारे देश में किसानों में भी एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है, जो इतना बोझ सहन कर सकता है। गुजरात के जिस एरिया से मैं आती हूँ, जहां मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहां के किसान बहुत जागृत हैं और वह इलाका बहुत सेन्सिटिव है। मेरे ख्याल से वे इस टैक्स की घोषणा के बाद इतने परेशान नहीं हैं और इसके प्रति उनका इतना विरोध नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, हमारे देश में किसानों में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है, जो कुछ न कुछ टैक्स सहन कर सकता है और उन्हें डेवेलपमेंट का जो लाभ मिला है, अगर उसमें से कुछ उन्हें देश के लिए देना पड़ता है, तो वह उसे देने के लिए तैयार होंगे।

वित्त मंत्री ने यह जो स्टेप लिया है, वैसा स्टेप शायद ही कोई मिनिस्टर ले सकता है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। आम तौर पर मिनिस्टरों को यह डर लगता है कि इस प्रकार का कदम उठाने से वे किसानों में अनपापुलर हो जायेंगे। इसी कारण हमारे देश की अधिकतर राज्य सरकारों ने आज तक इस टैक्स को छुआ तक नहीं और अपने बजट को डेफिसिट रख कर छोड़ दिया है। इस प्रकार यह सारा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट पर आ पड़ा है। किसानों में अनपापुलर होने की सम्भावना होने पर भी मोरारजी भाई ने यह सारा बोझ अपने कन्धे पर ले लिया है, जिस के लिए वह बधाई के पात्र हैं।

फर्टलाइजर पर टैक्स लगाने के बारे में माननीय सदस्यों ने जो राय प्रकट की है, मैं उस से सहमत हूँ। फर्टलाइजर को बड़े किसान तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अब छोटे किसानों ने भी उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसलिए अगर दो एकड़ जमीन वाले छोटे किसान भी फर्टलाइजर का उपयोग करें और बीस एकड़ वाले जमींदार और बड़े किसान भी उसका उपयोग करें और इस टैक्स से उन दोनों पर एक जैसा बोझ पड़े, तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार बड़े किसानों और जमींदारों से भले ही टैक्स ले ले, लेकिन जो छोटे किसान फर्टलाइजर का उपयोग करना चाहते हैं, अगर उन पर भी इस टैक्स का बोझ पड़ता है, तो इससे उनका इनसेन्टिव कम हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री महोदय को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए।

जहां तक शूगर पर टैक्स लगाने का संबंध है, मैं चाय पीने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज चाय एक ऐसी चीज बन गई है, आम लोग जिस को

[श्रीमती जयाबेन शाह]

बहुत ज्यादा पीते हैं। यह दलील दी जाती है कि गरीब लोगों को चीनी का जो राशन मिलता है, वे उसमें अपना काम चला लेते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तव में गरीब लोग चाय में गुड़ मिला कर चाय पीते हैं। और मेरे ख्याल से दूध और चाय और गुड़ मिलाना अच्छी चीज नहीं है हेल्थ के लिए। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि आप उनको देखिए कि यह बोझा गरीब पर पड़ता है। अगर वह गुड़ की चाय तो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। इतना टैक्स लगाने से इस चीज का कितना दाम बढ़ा है यह आप रिटेल शाप्स में जा कर देखिए। मेरी यह राय है कि ओपेन मार्केट में भी जो शूगर है उस पर कर लगाना उचित नहीं था।

एक छोटी सी बात जो हमारे और फ्रेंड्स ने नहीं बताई है वह मैं रखना चाहती हूँ। 197 एन्क्वायरी जो है टेलीफोन की उस पर जो आप ने चार्ज लगाया है, यह वैसे तो बहुत छोटी बात है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा यह जो टेलीफोन का एस्टेब्लिशमेंट है यह इतना इनएफिशियेंट है कि अगर हम को कोई नया टेलीफोन नम्बर चाहिए, कोई एन्क्वायरी चाहिए तो मिलना इतना मुश्किल है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। वह कहते हैं कि दूसरे देशों में हर एक जगह एन्क्वायरी पर पैसे लगते हैं। यह हो सकता है लेकिन वहां की एफिशियेंसी और हमारी एफिशियेंसी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैं यह कहती हूँ कि जब तक हमारा यह डिपार्टमेंट एफिशियेंट न हो तब तक यह पैसा लेना बिलकुल गैर-मुनासिब है और मेरे ख्याल से यह सबस्क्राइबर को असुविधाजनक है। तो इस के बारे में भी सोचिए।

अब मैं सबसे बड़ी चीज पर आती हूँ कि प्लानिंग कमीशन ने बार-बार यह आग्रह रखा है कि यह जो गत सालों में ऐग्रोकल्चर में इर्रीगेशन और एलैक्ट्रिसिटी के द्वारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका प्लाऊ बैक मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे प्लानर जब बैठते हैं सोचने के लिए तो उनके सामने पता नहीं कौन सा किसान आता है? यह बड़े-बड़े किसान जो हैं, जो बड़े-बड़े जमींदार हैं वह उनके सामने आते होंगे या ऐसे किसान आते होंगे कि जिनके यहां व्यापार भी होता है और जमीन भी होती है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का एक एवरेज किसान बहुत छोटा किसान है। हमारे यहां 50 परसेंट से ज्यादा जमीन-होल्डर ऐसे हैं कि उनके पास पांच एकड़ से नीचे जमीन है तो इनके बारे में तो यह सोचना पड़ेगा कि हम उनको कैसे मदद पहुँचा सकें। आज देहात में ऐसी हालत हो गई है कि कुछ लोग जिनके पास जमीन थी, जो बड़े जमींदार थे, लैंड रिफार्म्स आने के बाद भी जिन्होंने जमीन इधर उधर करके रख ली उनको इस सारे विकास का पूर्ण लाभ मिला है, उनको सब्सिडी मिली है, उनको लोन्स मिले हैं। उनको सब कुछ मिला है। मगर जो हमारे छोटे किसान हैं, जो हमारे देश के बैकबोन हैं उन को बहुत कम लाभ पहुँचा है। तो मैं प्लानिंग कमीशन से वित्त मंत्री के जरिए यह प्रार्थना करूंगी कि इसके बारे में सोचें अगर हो सके तो उनकी मदद करें। उनको यह सोचना चाहिए कि किसान कैसे ऊपर उठे। जब तक वह ऊपर नहीं उठेगा तब तक हम अन्न के उत्पादन में सेल्फ सफिशियेंट नहीं होने वाले हैं। आप कहते हैं कि 75 में हम सेल्फ सफिशियेंट बन जायेंगे। मेरे ख्याल से यह केवल धोखेबाजी है। जब तक हमारे एग्रीकल्चर में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती थी कि यह हमारे देश में जो कुछ प्लान बना तीन-तीन पंच वर्षीय योजनाएं बन गई, चौथी बनने में तो बहुत गड़बड़ी हो गई, हो सकता है कि तीन प्लान का यह परिणाम है कि हम चौथी प्लान नहीं बना सकते हैं। वित्त मंत्री के काम में कोई गलती है यह मैं नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे मौके पर तो हम आ गए कि आगे हम प्लान नहीं कर सकते। आज

देहातों में एक ऐसा वर्ग है जिसको हम वीकर सेक्शन कह सकते हैं। उनकी हालत ऐसी है कि आज उनको दो दफा पेट भर पूरा खाना भी नहीं मिल सकता है और हाउसिंग का सवाल तो अलग रहा। जब खाना नहीं मिलता तो हाउसिंह का सवाल कहां आ सकता है? उसमें बेकार भी हैं, अर्द्ध-बेकार भी हैं। मैंने इतना सारा बजट पढ़ा मोरार जी भाई जैसे व्यक्ति के हाथ में वित्त मंत्रालय है और यह गांधी जी के भक्त हैं, उनको मैं मानती भी हूँ और जानती भी हूँ, तो उनसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई योजना क्यों नहीं आती है कि जिसमें नीचे से हमारी प्लान बने और नीचे से काम चले? हमेशा बड़ी-बड़ी बातें कही जाती है कि यह जो प्लान बन रहा है, धीरे-धीरे इस की एकोनामी परकोलेट होकर नीचे तक पहुंच जाएगी और लोग ऊपर उठेंगे। मगर यह धोखेबाजी हो रही है। यह परकोलेट तो हुई नहीं जैसे शिव जी की जटा में गंगा जी जा कर समा गई ऐसे ही इस देश के 10 परसेंट, 20 परसेंट जो लोग हैं उनकी जटा में ज्यादातर वेल्थ जा कर बस गई है। हमारा जो वीकर सैक्शन है जो गरीब हैं, हरिजन हैं, मध्यम और नीचे के इकोनामिक स्तर के लोग हैं, उनके पास यह नेशनल वेल्थ बहुत कम पहुंची है। तो मैं प्रार्थना करूंगी-- अगर मोरार जी भाई यहां होते तो अच्छा था, गांधी जी ने कहा था कि जब कोई काम करो तब दरिद्रनारायण को नजर में रख कर काम करो। जब देश का प्लान पहली दफा बनने जा रहा था, तब बिनोबा जी को भी प्लानिंग कमिशन ने बुलाया था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप इस तरह का प्लानिंग सोचें जिसमें नीचे का आदमी ऊपर उठ सके, उसी स्थान से अपने प्लानिंग को शुरू करो। लेकिन आज आप देखें कन्ज्यूमर गुड्स इतना मंहगा होने पर मिलता ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास वेल्थ बढ़ी है, वे सारे का सारा कन्ज्यूमर गुड्स खरीद सकते हैं, गरीब लोग इतने हार्ड-हिट हैं कि वे खरीद ही नहीं सकते। जो बीच के लोग हैं, जिनकी आमदनी बंधी हुई है, जिनकी हालत इयनी ज्यादा खराब है --जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर हम कहते हैं यह डेमोक्रेसी है—मैं डेमोक्रेसी में पूरी श्रद्धा रखने वाली हूँ—लेकिन अगर हम जनता को इस डेमोक्रेसी में रोटी न दे सकें, हाउसिंग एकोमोडेशन न दे सकें तो हमारी श्रद्धा या लोगों की श्रद्धा, चाहे हम कितनी कोशिश करें, डेमोक्रेसी में नहीं टिक सकती।

मैं उम्मीद करती थी कि इस बजट से एक नया मोड़ आयेगा, जिससें हमारे गरीब लोगों को कुछ दिलासा मिल सकेगा, तसल्ली मिलेगी कि हमारा भाग्य भी खुल रहा है। जब जब पंचवर्षीय योजना बनती है हम बताते हैं कि इतने आदमियों को रोजगार मिलेगा, और इतने बेकार रहेंगे, लेकिन मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहती हूँ कि हमारे गरीब और भूखे लोग अनिश्चित काल तक इन्तजार करके नहीं बैठेंगे, वे डेस्प्रेट होकर जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

सभापति महोदय, आप विलेज एरिया से आते हैं, आप जानते हैं कि वहां लोगों की क्या हालत है, उनके पास पूरे समय के लिए काम नहीं है, इण्डस्ट्रीज नहीं बढ़ी है, डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ इण्डस्ट्रीज नहीं हुआ है, लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। शहरों की क्या हालत है—मैंने कलकत्ता में देखा कि गटर से गंदा पानी ओवर-फ्लो हो रहा है, गारबेज के ढेर के ढेर पड़े हुए हैं और उन्हीं में लाखों लोग बेघर पड़े हुए हैं। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, बम्बई और तमाम बड़े-बड़े शहरों की यही हालत है, क्योंकि रूरल एरियाज की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। रूरल एरियाज में काम न होने के कारण लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं, जिससे शहरों में सेनिटेशन का सवाल खडा होता है, हाउसिंग का सवाल खड़ा होता है, जिसके कारण दंगे मच रहे हैं, लोगों में फस्ट्रेशन फैल रहा है। हमारे यूथ्स में जो फस्ट्रेशन आया हुआ है उसका क्या कारण है? उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि उनके दिल को तसल्ली नहीं है कि कभी

[श्रीमती जयाबेन शाह]

हमारा नसीब भी खुलेगा, उनको कोई आशाजनक तस्वीर सामने नहीं आती है।

सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों बिहार और दूसरी जगहों पर गई थी, मैंने देखा कि वहां की लैंड अच्छी है, पानी अच्छा मिलने पर भी खेती नहीं होती है, बार बार अकाल पड़ता है। राजस्थान में अकाल पड़ा, मेरे यहां गुजरात में भी पड़ा। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहती हूँ—फाइनेन्स कमीशन ने अपने सुझाव सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दिये हैं, मैं चाहती हूँ कि राज्यों की सहायता के मामले में आप ऐसी कन्डीशन बनायें कि जिस स्टेट के लोग, उनके मंत्रीगण ऐसा वायदा करें कि हम अपने यहां लैंड रिफौर्म करेंगे, सोशल रिफोर्म करेंगे, उनकी आप ज्यादा मदद करें। गुजरात के बारे में आपने क्या किया —आपने उनकी सहायता काट ली। आप कहते हैं कि वह आगे बढ़ा हुआ स्टेट है। वह आगे कैसे बढ़ा है वहां के किसानों ने मेहनत की है, वहां की सरकार ने किसानों की मदद की लैंड, रिफार्म और शोशल रिफौर्म किए, इसलिए आगे बढ़े हैं। चूंकि वह आगे बढ़े हैं, इसलिए आप कहते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा—यह पालिसी गलत है, इससे लोगों के इन्सेन्टिव को आप कम कर रहे हैं। यह केवल गुजरात का ही सवाल नहीं है, यह नेशनल सवाल है, सारे देश का सवाल है। हमारी नर्मदा के बारे में बहुत चर्चा होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर दो साल पहले यह काम हो जाता, तो इससे कितना अन्न पैदा हो सकता था, मगर ऐसा नहीं होता है।

इसी प्रकार से पेट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज की बात है और आफ शोर ड्रिलिंग की बात है। ऐसे बहुत से नेशनल सवाल हैं जैसे कि मीठापुर की योजना है। ये सारे नेशनल प्लान्स हैं और इसी दृष्टि से इनको देखना चाहिए। हर एक बात में साल, दो साल, पांच साल और दस साल बीत जाते हैं और उससे देश का बहुत नुकसान होता है। जब हम अन्न के दाने दाने के पीछे मरते हैं तब क्या हम ऐसी स्कीमें नहीं बना सकते हैं ?...(व्यवधान)...हमारे सेठी साहब भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वे भी इस बात को देखें। ये योजनाएं सारे देश की योजनाएं हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वे इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके।

18.00 hrs.

आज सबसे बड़ी बात यह है कि यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। मुझे अफसोस होता है कि इस वर्ष के बजट में हमारे मोरारजी भाई ने ऐसी ग्राम योजनायें क्यों नहीं रखीं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का प्रबन्ध किया जायेगा। आज देश का नक्शा बदल रहा है, दिमाग भी बदल रहा है। जब हम गांधी जी का नाम लेते हैं तो फिर हमें इस देश में नये विचार से परिवर्तन लाने काम शुरू करना पड़ेगा। परन्तु ऐसी बातों का रेपलेक्शन इस बजट में नहीं दिखाई देता है जिससे लोगों को तसल्ली हो और आज देश के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वह दूर हो।

सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Public memory is short. I was talking to some people just two years ago when I entered this Parliament. I made a statement then that the Congress President, Shri Nijialingappa, is the last Congress President who is going to liquidate the Congress organisation. Of course, it is not my business to say it here.

MR. CHAIRMAN : Speak on the budget.

SHRI K. LAKKAPPA : That was why I said it is not my business to say this.

SHRI SAMBASIVAM (Nagapattinam) : What is he talking about ? How is this relevant ?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): The PSP has already been liquidated. Let him bother about his party's fate.

SHRI K. LAKKAPPA: Here is a Finance Minister who is going to liquidate the finances of this country. If we take the taxation measures here from 1947, we come across many Finance Ministers, their resignations and their episodes. Here is a man who goes on increasing taxes, who sticks to his bureaucratic principle of taxing the country very heavily.

Shri Palkhiwala, an authority on taxation, has calculated by statistics that India is the only country which is so heavily taxed. This is the socialism they want to celebrate in the Gandhi Centenary year.

In the name of Gandhi Centenary, I want two revolutions in this country. One is to fight out unemployment and the other is to bring about a revolution in the agricultural field.

What is the social revolution indicated by the Finance Minister to this country. He has a cruel heart towards the farmers of India who represent eighty per cent of the population. He has taxed fertilisers. We are not even self-sufficient in fertilieers and they contemplate importing fertilisers from abroad. Fertiliser factories are not allowed to be started, even if they are sponsored and collaboration agreements had been arrived at. This is the kind of agricultural economy which the Congress Government advocating socialism wants to build. Our needs of nitrogenous fertilisers are 1.7 million tonnes of which we produce only 0.55 million, resulting in the import of 1.05 million tonnes. We need 0.65 million tonnes of phosphatic fertilisers of P. O. 2.5 We produce 0.23 million tonnes and our imports are 0.14 million tonnes. Similarly we need potassic fertilisers of 0.45 million tonnes. We do not produce anything at all and we can import only 0.213 million tonnes of K20. This is not a budget aimed at furthering socialism; it is business-oriented and gives export incentive and is meant to help big business houses. The Hazare report had been rejected. I doubt even whether Mr. Desai would reply to this debate because his position is in the doldrums. There is coldwar going on inside the Congress between the industrialist and monopolist groups in the Congsess.

Article 263 speaks of co-ordination between the States and the Centre. I represent one of the Southern States. I can quote figures to prove how the southern States had been neglected by the North Indian rulers, specially U. P. which had been ruling India all along through Nehru. The irrigation facilities provided in Mysore State are the worst, they are worse than Rajasthan. In the matter of public sector investments, from 1951-52 to 1967-68, over Rs. 2,400 crores had been invested but Mysore's share is only Rs. 48 crores. Even expansion schemes of the ITI and BEL had been taken away from Mysore by a conspiracy to take things away from Mysore. Krishna and Godavari disputes had been referred to the Tribunal and they are hanging in the air. Politics come into play even clearance is not given to certain schemes, such as the Mangalore fertiliser factory. Both the Congress and the non-Congress Chief Ministers welcome the suggestion made under article 263; I mean that even Shri Brahmananda Reddi who is a Congress Chief Minister had made this point.

We want a permanent Commission to meet out justice with respect to all financial allocations and the resources with respect to the development of all backward States in the country. Its duty must be: "making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject;" And

> "it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure."

So far, after 20 years of rule by the Congress Government, the Congress Government has not made any progress in this respect in order to give a uniform development to the country and all the States. I want all the financial allocations to the States to be made on the basis of population. For that alone, an independent Commission should be appointed. Some Finance Commission headed by Shri Mahavir Tyagi will not suffice. All the suggestions made by the States have not been agreed to by him. Therefore, with these suggestions, I resume my seat.

[Shri K. Lakkappa]

One small point, and I have done. The Ministry is taxing the people heavily. There are a number of problems pertaining to the States, and a number of problems with respect to border disputes between Maharashtra and Mysore. The Congress Working Committee has been scheduled to meet to take a decision on the Mahajan Commission report and it has perpetually played a fraud, yielding to the tactics played by this venomous cobra of the country, the Home ministry, under Mr. Chavan who is using all unconstitutional methods. (*Interruption*).

AN HON. MEMBER : Wrong.

SHRI K. LAKKAPPA : You better resign from the Congress and join the Opposition. Let us all go and join the Opposition parties. You have no business to say that it is wrong.

MR. CHAIRMAN Order, order. Please conclude.

SHRI K. LAKKAPPA : This has been hanging fire ; is this country going to give the impression that we have to adopt violence in this country ? Because, Mr. Chavan has been nursing the Shiv Sena which has created fraud, arson, looting of the South Indians ; they have done a barbarous act under the very nose of Mr. Chavan, and so I call him**.

MR. CHAIRMAN : The allegations made by Mr. Lakkappa against Mr. Chavan have already been refuted. Therefore, they may be xpunged.

SHRI K. LAKKAPPA : Why should it be expunged ? (*Interruptions.*)

MR. CHAIRMAN : Order, order. Please take you seat. Please take your seat first. Once the allegation was made ; twice the allegation was made. It was refuted a number of times. How long will you continue like that ? One cannot continue to make an allegation like that.

SHRI K. LAKKAPPA : I did not make any allegation at any time, calling him as**, that is, Mr. Chavan, at any time. Therefore, this is the first time that I am calling him as**

MR. CHAIRMAN : That will be expunged. (*Interruptions*.

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry) : It will be there on the record.

SHRI RAJASEKHARAN (Kanakapura): Sir, I must congratulate our Finance Minister and Deyuty Prime Minister on his having tried to present the best possible budget out of the existing situation. He has tried his best to consolidate the gains which have been made during the recent months. While doing so, the Finance Minister has been very harsh to the farming community. The vitals of our country are being eaten away every day by our unproductive labour force and the inefficient Government employees. Whatever resources the Finance Minister has been able to mop up are being drained away in paying more wages to the labour force and more dearness allowance to the inefficient employees. It looks to me as though this country and this Government are only existing to feed the unproductive labour force and the inefficient Government employees. The labour force in our country unfortunately is most unproductive and costly.

It was mentioned in this House the other day with regard to Bhilai and Bokaro that we are employing 18000 to 20000 people to produce I million tons of steel, whereas in Japan they employ only 2,000 people. This creats a doubt whether we are producing steel or silver in these steel plants. We have invested about Rs. 2400 crores in our public sector. I know public sector is essential and after sometime, they will take care of the productive aspect of our country. But at present, we have spent much of our capital on unproductive things. About Rs. 80 crores are invested on building palatial houses for the executives in the public sector industries. At least hereafter such expenditure should be avoided.

Our public sector industries are suffering for want of efficient executives. Unfortunately, we have trusted our administrators too much and not entrusted these things so technocrats. At least hereafter, technocrats

**Expunged as ordered by the Chair.

should be put heads of public sector industries. The present administrative system is most unsuited to our country. Before the independence, it was taking care of law and order and collection of revenue and the samething is being continued now. It is not production-oriented. This should be remedied as early as possible.

There has been much delay in taking decisions, due to which the project cost are increasing every day. Most of our resources are being drained away in this manner. To give a benefit worth one rupee to the people, we spend Rs. 4 on the administration. This should be taken care of.

We have been hearing from the very beginning that agriculture will receive top priority, but if we see the allocations made in all the plans, agriculture has not received top priority. In the fourth plan, for instance they have allotted only 20.6 per cent to agriculture whereas industry gets 24.8 per cent. 50 per cent of our national income comes from agriculture sector. It employes about two-thirds of the labour force in our rural areas. It contributes two-third to our export earnings. But still it is not receiving proper treatment from the Government. The rural people are living in a very miserable way. They do not have good roads, good houses, enough drinking water, good lighting facilities, etc. I understand the average earning of a villager is about 50 paise per day. How can the Government put taxes on the farmers when this is their plight ? Unfortunately, Government is putting a levy on fertilisers. In 1966, after devaluation, the cost of fertilisers went up by 57.7 per cent. Now we are putting more taxes on it. At this cost, can our farmers purchase fertilisers ? Every year more and more farmers are begining to use fertilisers. So, we must make it available to them at cheaper rates.

As you are aware, Sir, one tonne of fertiliser put to the land would ordinarily give two tonnes of foodgrains. Therefore, I would advocate to the Finance Minister to consider withdrawing this levy on fertilisers.

I would now come to the agricultural taxation which the Finance Minister has included in his budget proposals. To justify this he said that some people who have got black money invest it in agriculture in an attempt to convert their black money into white money. If it is so, let Finance Minister bring forward a separate legislation toc urb that. Why should he penalise thousands of millions of farmers who are contributing to the production in this country ?

Much has been said about the green revolution. I would like to submit to the House that most of the people who are talking about it do not know how in the countryside a plant is grown. You must understand that the plants are exposed to the vagaries of nature and a lot of diseases would affect them in that period. All these things the farmer has got to fight against and increase his production. Even if he gets a good production he will not get a good price. Unfortunately, our Government has not come forward to give price support to all the produces that the farmers are growing in this country. I wouid just quote what Dr. Ashok Mitra, Chairman, Agriculture Prices Commission, has said about the green revolution. He wrot in *The Statesman* of October 14th and 15th :

> "Foodgrain production in 1967-68 has been excellent : optimism has accordingly filled the air, fostering a widespread impression that the agricultural revolution is more than three quarters accomplished, Much of this optimism is owing to the increase in this year's wheat output over last year's by almost 45 per cent; compared with our previous best achievement, which was in 1964-65, the increase in the production of wheat this year is nearly 35 per cent.
>
> And yet, it will not do to lose sight of some of the other elements in the situation. As Table I shows despite this year's record output, the compound rate of growth of output of all foodgrains, with 1950-51 as base, is hardly 2.25 per cent. This is not even enough to keep pace with the annual rise in population. What is more, a substantial part of this modest growth was in fact achieved during the 1950s. The rate of growth for the period 1949-50 to 1958-59 was as high as 3,29 per cent per annum; in contrast that for the last ten years has been only 0.67 per cent per annum. Even for wheat, the stupendous strides registered this year merely mean that we are still struggling to return to the trend line of growth reached earlier, around 4 per cent per annum."

This would reveal that we have not really made our green revolution successful

[Shri Rajasekharan]

We have just started. As you are aware, the new startegy in agriculture has just started. We have started implementing it since 1966-67. I would, therefore, request the Finance Minister to give a complete tax-holiday for our agricultural sector at least for ten to twenty years. We have been proposing tax-holidays to the industrial sector. We are giving development rebate to the industrial sector. We have been giving a lot of concessions to the industrial sector. Why not we give this particular sector, the agricultural sector, a tax-holiday ? This sector has suffered for years together. This sector deserves a good treatment at least now at the hands of the Government.

If the money is put in the pockets of our formers those people will be the biggest c mmon market in our country. They are prepared to consume most of our iudustrial production, most of our consumer goods. In Japan, whieh is a a highly industrialised country, about 80 per cent of its products produced by them are consumed by the farmers in Japan itself.

So. our rural population will be the biggest market for all our industrial output and the consumer goods in our country. Therefore, let the government give more a attention to agro-based industries in this country so that the employment potential will increase.

Then I would say that the government should immediately come forward with a price support policy, so far as agricultural products are concerned. Now what unfortunately happens is that the farmer puts all his efforts and makes a good produce. But he is not able to get a good price, because he is at the mercy of the middlemen. This should go. For that the government should come forward with a strong agricultural price support policy. The earlier it is done the better it will be for ihe farmers.

Here I would like to say what other countries are doing in this connection. Take the case of Japan. Every year Japan is spending about 200 billion yen for giving price support to paddy. We should certainly emulate this example.

Then I would like to point out to the Finance Minister that agricultural development depends greatly on research. The success of new startegies and strains which we are discussing on the floor of the House and which we are reading in newspapers depend on agricultural research. But what are we doing for agricultural research ? We are allotting hardly ten per cent of our science budget on agticultural research whereas countries like Australia and New Zealand are spending 45 per cent of their science budget on agricultural research. I would appeal to the Finance Minister that at least during the Fourth Plan period substantial amounts should be set apart for agricultural research.

Then I come to regional imbalances. During the period 1951-52 to 1967 68 we have made an investment of Rs. 2,400 crores in the public sector. How much of it has gone to Mysore ? Only about Rs. 48 crores Though we have been talking much about giving proper or better treatment to States which are baekward, these figures would indicate that the Centre has not treated all backward States on an equal footing.

In this connection, I would like to make one suggestion. I understand that the government is thinking of setting up a second unit of Bharat Electricals and Indian telephone Industries. Technical opinion has been in favour of setting up these industries in the Southern States because they want the area to be cool and dust-free. The technical committee has given a clear opinion that they should be set up in the area where they are already working. Here I may say that there is already a move to get these industries located in Uttar Pradesh or some other northern State. I would plead with the Finance Minister to see that these industries are set up in an area where they will be able to produce in an economic way.

SHRI M. SUDARSANAM (Narasaraopet) ; Mr. Chairman, Sir, in a developing country like ours, the budget has a tremendous impact on the economy of the country.

MR. CHAIRMAN ; He may continue his speech tomorrow. We will now take up ths half an hour discussion.

18.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

General Motors Corporation of U.S.

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Mr.